सांध्य दैनिक 4PM

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 12 ● अंक: 38 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शुक्रवार 13 मार्च, 2026

मूल्य ₹ 3/-

दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो।
-स्वामी विवेकानंद

सनराइजर्स लीड्स ने पाक खिलाड़ी पर... 7 | मेक इन इंडिया की खुली... 3 | नकली संतों का दौर खत्म होगा... 2

सियासी दलों की हुंकार

मौजूदा संकट के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार!

» पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर की बात लेकिन संकट बरकार

» बोला विपक्ष- एलपीजी की यदि नहीं है कमी तो फिर सिलेंडर के लिए मारामारी क्यों?

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। क्या सरकार सिर्फ आश्वासन के सहारे काम चला रही है? क्या हकीकत और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है? यदि गैस होती तो फिर लोग लाइन में क्यों होते? यदि स्टाक होता तो फिर बुकिंग के नियम क्यों बदले गये होते।

यह बात अब किसी एक राजनेता की नहीं रही बल्कि देश के सभी विपक्षी दल एलपीजी किल्लत के लिए सीधे पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शुरूआत आप नेता संजय सिंह के संसद सत्र में दिये गये बयान से शुरू हुई जो अब धीरे-धीरे आमजन की जुबान पर चढ़ती दिखाई दे रही है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी सुरक्षा का दावा

मध्य पूर्व के बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजरें अब उस समुद्री मार्ग पर टिक गई हैं जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यह मार्ग है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसे ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है। इस पर ईरान का कब्जा है और उसने आसपास के समुद्री क्षेत्र में बारूदी सुरंगे भी बिछाना शुरू कर दी है। वही उसकी मानवरहित आत्मघाति बोट का जलवा पूरी दुनिया मानती है। ऐसे में ईरान की धमकी के बाद से वहां से जहाजों का आना जाना लगभग रूक चुका है और जो भी जहाज गुजरने की कोशिश कर रहे हैं वह स्वंय के रिस्क पर आगे बढ़ रहे हैं। सूचना के मुताबिक अतबक उस क्षेत्र में 28 भारतीय जहाज रूके हैं। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि अमेरिका इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा दी गई है ताकि तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों को किसी भी तरह के हमले से बचाया जा सके।

आस्तीने ताने विपक्ष, बैकफुट पर सरकार

आप नेता संजय सिंह के ताजा आरोपों से देश की सियासत में भूचाल आ चुका है। ईरान-इजरायल युद्ध के चलते भले ही मिडिल ईस्ट में बर्बादी के बादल घिरे हो लेकिन अपना भारत भी संकट से अछूता नहीं रहा। अब तो देश के दूसरे सियासी दल भी मौजूदा संकट के लिए आस्तीने ताने सीधे पीएम मोदी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। पीएम मोदी के ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात करने के बावजूद जमीनी स्तर पर संकट कायम रहने पर विपक्षी दलों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि पीएम मोदी की नीतियों की वजह से ही महंगाई और आवश्यक वस्तुओं विशेषकर एलपीजी सिलेंडर की मारामारी बढ़ी है। विपक्ष का कहना है कि ईरानी राष्ट्रपति से बात होने के बाद भी जनता को राहत नहीं मिली और एलपीजी की किल्लत अभी भी जारी है जबकि सरकार दावे कर रही है।

मोदी-ईरान वार्ता, बयान नहीं राहत चाहिए

मध्य पूर्व के तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने कूटनीतिक सक्रियता भी बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान से फोन पर बातचीत कर क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसके वैश्विक असर पर विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर दिया। भारत का रुख पारंपरिक रूप से संतुलित माना जाता है। एक तरफ उसके ऊर्जा और व्यापारिक हित खाड़ी क्षेत्र से जुड़े हैं दूसरी तरफ वह वैश्विक स्तर पर स्थिरता और शांति का समर्थक भी रहा है। इसी वजह से भारत लगातार कूटनीतिक प्रयासों के जरिए तनाव कम करने की अपील कर रहा है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि कूटनीतिक बातचीत अपनी जगह है लेकिन देश के अंदर गैस और ईंधन से जुड़ी समस्याओं पर भी सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उनके मुताबिक जनता को केवल बयान नहीं बल्कि राहत की जरूरत है।

ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली दर्द बाकी है : राहुल

लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार की रुकावट या बंद होने से भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति सीधे तौर पर प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंता पहले से ही फैल रही है और संघर्ष बढ़ने पर यह और भी गंभीर हो सकती है। ऊर्जा सुरक्षा को किसी भी देश के लिए मूलभूत बताते हुए गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि भारत को अमेरिका को इस बात पर प्रभाव डालने की अनुमति क्यों देनी चाहिए कि वह गैस कहां से खरीदे। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम होंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य, जिससे वैश्विक तेल का 20 प्रतिशत प्रवाह होता है, बंद कर दिया गया है। इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे, खासकर हमारे लिए, क्योंकि हमारे तेल और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। रेस्तरां बंद हो रहे हैं। एलपीजी को लेकर व्यापक दहशत फैली हुई है... यह तो बस शुरुआत है।

पीएम मोदी सही हैं लेकिन स्थिति पर संदेह है : प्रियंका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से घबराहट न करने का आग्रह करने और यह कहने के एक दिन बाद कि भारत कोविड महामारी की तरह ही एलपीजी सिलेंडर संकट से उबर जाएगा, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी सही हैं, लेकिन स्थिति पर संदेह व्यक्त किया। देशव्यापी एलपीजी की कमी की खबरों के बीच पीएम मोदी के आश्वासन पर कांग्रेस सांसद ने पत्रकारों से संक्षेप में कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह सही हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है।

भारत-अमेरिका खनिज समझौते की दिशा में बढ़ते कदम

वैश्विक तनाव और ऊर्जा संकट के बीच भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग भी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर के मुताबिक दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े एक बड़े समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। यह समझौता उन खनिजों पर केंद्रित है जो आधुनिक तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा उपकरणों के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सहयोग से दोनों देशों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सकती है और चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। भारत के लिए यह समझौता रणनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है क्योंकि ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना उसकी प्राथमिकता बन चुका है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि वैश्विक समझौतों के साथ-साथ सरकार को घरेलू संकटों पर भी उतनी ही तेजी से ध्यान देना होगा क्योंकि आखिरकार जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल वही है कि रसोई में सिलेंडर कब और कैसे पहुंचेगा।

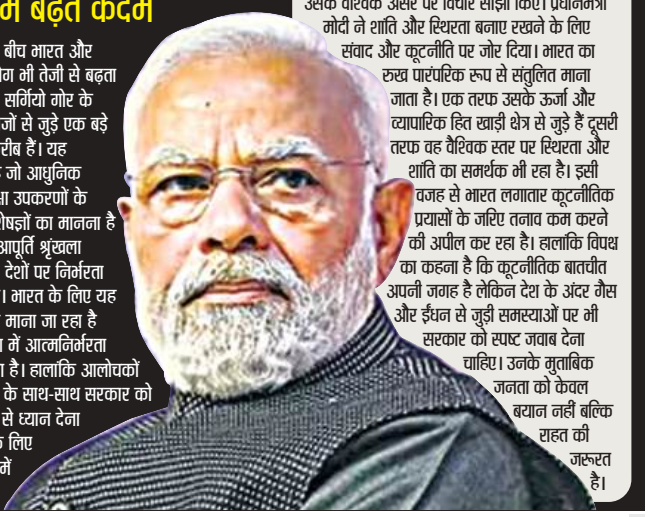

नकली संतों का दौर खत्म होगा : अखिलेश यादव

» सपा प्रमुख अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने के बाद भाजपा पर बरसे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा प्रमुख ने एकबार फिर भाजपा पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि शंकराचार्य के आशीर्वाद से नकली संतों के प्रभाव को उजागर करने और समाप्त करने में मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज में वास्तविक आध्यात्मिक मार्गदर्शन का महत्व बना हुआ है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यादव ने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना हमेशा शुभ माना जाता है। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि वे मुख्य रूप से शंकराचार्य का आशीर्वाद लेने आए थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह यात्रा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से संबंधित है, तो उन्होंने जवाब दिया कि राजनीति में लोग अक्सर खुलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, खासकर सोशल मीडिया के युग में, लेकिन उनकी यह यात्रा केवल पूज्य संत से आशीर्वाद लेने के लिए थी।

हरियाणा में जेजेपी की रैली, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव करेंगे शिरकत

जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला के जन्मदिवस पर आज नई अनाज मंडी में मनाए जाने वाले हरियाणा जनचेतना दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव, मुज्जफरनगर से सांसद हरेंद्र मिलक, राजस्थान के शिव (बाड़मेर) विधानसभा से विधायक रविंद्र भाटी व उत्तराखंड के रायपुर हलके से विधायक उमेश शर्मा पहुंचेंगे। रैली में कई सामाजिक संस्थाओं, खापों, खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। वीरवार को रैली स्थल का जायजा लेने के लिए जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला दिनभर नई अनाज मंडी में डटे रहे। रैली में व्यवस्थाएं संभालने के लिए जेजेपी की छात्र इकाई इनसो के 500 वॉलियंटर की ड्यूटी लगाई गई है।

अपने कार्यकाल मैने गौ दुहने का संयंत्र कन्नौज में लगवाया था

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ संरक्षण अभियान के तहत एक दिन पहले लखनऊ पहुंचे थे। इस बातचीत के दौरान यादव ने बताया कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का पहला गौ दुहने का संयंत्र कन्नौज में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्थापित किया गया था। यादव ने आगे बताया कि उनके परिवार में बचपन से ही गायों की देखभाल करने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि आज भी घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को अर्पित की जाती है।

राज्य चुनावों से पहले बीजेपी के भीतर टिकट रद्द हो रहे हैं

राजनीतिक घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर टिकट रद्द होने की खबरें आ रही हैं। उनके अनुसार, कई जिलों में बैठकें हो रही हैं जिनमें यह तय किया जा रहा है कि किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा और किनके नामांकन रद्द किए जाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दोनों उपमुख्यमंत्रियों को फटकार लगाने पर चर्चा हो रही है और संकेत दिया कि उन्हें अपनी सीटें जीतने में मुश्किल हो सकती है। सपा चीफ ने लिखा कि बीजेपी की ग़लतियों का ख़ामियाज़ा जनता क्यों भुगते? सत्ताधारी बीजेपी और झूठी सेवा का 'शताब्दीय' दावा करनेवाले उनके अनरजिस्टर्ड संगी-साथी भूख से तड़प रहे लोगों के लिए मुफ़्त भोजनालय चलाएं; नहीं तो नज़र न आएं।

नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार सभी विकास सूचकांकों में पिछड़ा : तेजस्वी यादव

इन शर्मनाक तथ्यों और रैंकिंग के लिए किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में राज्य ने सभी विकास सूचकांकों पर सबसे खराब प्रदर्शन किया है। तेजस्वी का यह हमला ऐसे समय में आया है जब नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा पर हैं और आरजेडी के शासनकाल के जंगल राज के विपरीत अपने शासनकाल में हुए बिहार के विकास की बात कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन शर्मनाक तथ्यों और रैंकिंग के लिए किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया। नीतीश और उनकी सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि बिहार एक अनूठा और अद्वितीय राज्य है जहां एनडीए की दो इंजन वाली सरकार दशकों से सत्ता में है, फिर भी यह देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां देश में सबसे अधिक पलायन, सबसे अधिक अपराध, सबसे अधिक भ्रष्टाचार, सबसे अधिक बेरोजगारी, सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी और साथ ही देश में सबसे अधिक स्कूली शिक्षा छोड़ने की दर है।उन्होंने आगे कहा कि दूसरी ओर, बिहार में देश में सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, सबसे कम किसानों की आय, सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश, सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग, सबसे कम कंप्यूटर साक्षरता, सबसे कम बिजली की खपत, सबसे कम बुनियादी ढांचा, सबसे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सबसे कम औद्योगिक इकाइयां और स्कूलों में कंप्यूटर और आईसीटी प्रयोगशालाओं की सबसे कम संख्या है।नीतीश सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए आरजेडी नेता ने कहा कि देश में विकास के सभी सूचकांकों में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है, शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं/सुविधाओं में सबसे खराब प्रदर्शन है, सबसे महंगी गैस, सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगे पेट्रोल-डीजल की खरीद में भी बिहार अग्रणी है। यह बताते हुए कि बिहार में दिल्ली-मुंबई से भी अधिक महंगी संपत्ति और जमीन है, उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के 21 वर्षों में बिहार विकास के सभी मानकों, मानदंडों और सूचकांकों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, लेकिन इन शर्मनाक तथ्यों और रैंकिंग के लिए किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया जाता—बस पलटी, प्रशासनिक तंत्र, सरकारी खजाने से वोट खरीदना, वोटों की लूट और जातिवाद का सहारा लेना ही एकमात्र विकल्प है, जबकि तथाकथित सुशासन के समर्थक सत्ता का आनंद ले रहे हैं।

नाले से गैस बन सकती है तो प्लांट का उद्घाटन करें पीएम : संजय राउत

» एलपीजी संकट के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद का तीखा हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे गलत साबित हो रहे हैं और एलपीजी और ईंधन की कमी का असर कई क्षेत्रों पर पड़ रहा है।

राउत ने आरोप लगाया कि कमर्शियल और घरेलू गैस की कमी के कारण कई जगह रेस्टोरेंट और दूसरी इंडस्ट्री प्रभावित हो रही हैं, यहां तक कि कुछ रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई है. उनका कहना था कि जब पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू हुआ था तब केंद्र सरकार ने कहा था कि इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अब हालात अलग दिखाई दे रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के आश्वासन गलत साबित हो गए हैं। संजय राउत ने कहा कि मुंबई और दूसरे शहरों में गैस की किल्लत के कारण रेस्टोरेंट बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं और इसका असर उद्योगों पर भी पड़ सकता है।

उन्होंने दावा किया कि वाहन क्षेत्र पर भी संकट मंडरा रहा है और गुजरात के मोरबी में टाइल उद्योग पर असर पड़ रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों पर इस मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगाया. राउत ने प्रधानमंत्री के उस पुराने बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें नाले से गैस बनाने के प्रयोग का जिक्र किया गया था और कहा कि अगर ऐसा संभव है तो मुंबई में ऐसे संयंत्र का उद्घाटन किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर भी टिप्पणी की और आरोप लगाया कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी तंज कसा और कहा कि उनके बारे में नई-नई दंतकथाएं सामने आती रहती हैं।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

वरिष्ठ नेता जी. सुधाकरन ने सीपीएम छोड़ी

» केरल विधान सभा में निर्दलीय ठोकेंगे ताल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोच्चि। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के लिए एक बड़ा झटका देते हुए, वरिष्ठ नेता जी. सुधाकरन ने घोषणा की कि उन्होंने पार्टी से सभी संबंध तोड़ लिए हैं और आगामी केरल विधानसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र अंबलप्पुझा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए सुधाकरन ने कहा कि वह अंबलप्पुझा के तटीय जिले में स्थित उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जिसे लंबे समय से सीपीआई (एम) का गढ़ माना जाता रहा है।

उन्होंने कहा, यूडीएफ से समर्थन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसके लिए अनुरोध नहीं किया है। मैंने किसी से बात नहीं की है। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि वह अपने चुनाव प्रचार के तहत दीवार पेंटिंग या सम्मेलन आयोजित नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने किसी का समर्थन नहीं मांगा है। उन्होंने यूडीएफ के समर्थन से चुनाव लड़ने की अटकलों को भी खारिज करते हुए ऐसे दावों को प्रचार बताया। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि कुछ नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन किसी भी वरिष्ठ पार्टी नेता ने उनसे सुलह के लिए संपर्क नहीं किया। सुधाकरन ने याद दिलाया कि उन्होंने 68 साल पहले स्कूल में पढ़ते समय ही सीपीआई (एम) में शामिल हो गए थे और 1967 में एसएन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पार्टी की राजनीति में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने कहा, मैंने किसी के दबाव में आकर पार्टी में शामिल नहीं हुआ। सुधाकरन ने बताया कि उन्होंने अपनी पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया है, जिसकी जांच सीपीआई (एम) शाखा समिति द्वारा की जाती है।

चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक मुद्दे उठाएंगे : सुधाकरन

सुधाकरन ने कहा कि वे चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक मुद्दे उठाएंगे, लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि वे भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। सुधाकरन ने कहा कि उन्होंने राज्य समिति को कोई शिकायत नहीं दी है और निचले स्तर पर ही मुद्दों को सुलझा लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री या पार्टी नेतृत्व से हस्तक्षेप या टिकट के लिए कभी संपर्क नहीं किया। अपने बारे में हालिया खबरों का जिक्र करते हुए सुधाकरन ने कहा कि मीडिया में उनके नाम से छपे कई बयान गलत हैं।

मेक इन इंडिया की खुली पोल

भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक

- भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक
- रूस पर नई दिल्ली की दशकों पुरानी निर्भरता में आई भारी गिरावट
- फ्रांस और इजराइल को सबसे अधिक लाभ
- 2021 से 2025 के बीच वैश्विक हिस्सेदारी 8.2 प्रतिशत रही

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कहां तो देश में डिफेंस कॉरीडोर बनाने में खरबों की धनराशि लगाई जा रही है। कहां तो भारत में ही बड़े -बड़े हथियार बनाने के दावे किए गए थे। उसके उलट एक रिपोर्ट ने आत्मनिर्भर भारत को करार झटका तो दिया ही है साथ ही मोदी सरकार की पोल खोल दी है। एसआईपीआरआई की रिपोर्ट भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीददार बना है। 2021 से 2025 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2 प्रतिशत रही, हालांकि 2016-2020 की तुलना में इस अवधि में भारत के आयात में 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

इस अवधि में भारत को सैन्य उपकरणों की सबसे ज्यादा आपूर्ति रूस ने की, लेकिन रूस पर निर्भरता लगातार घट रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की रक्षा खरीद और स्वदेशी निर्माण नीति का सामरिक महत्व बेहद गहरा है। एक ओर यह देश की सैन्य क्षमता को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक रक्षा साझेदारियों को भी मजबूत कर रही है। चीन और पाकिस्तान जैसी दोहरी सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत का सैन्य आधुनिकीकरण क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलने से देश की आर्थिक और तकनीकी शक्ति भी मजबूत हो रही है। इस प्रकार भारत न केवल दुनिया के प्रमुख हथियार आयातकों में बना हुआ है, बल्कि धीरे धीरे आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनने की दिशा में भी निर्णायक कदम बढ़ा रहा है।

मेक-इन-इंडिया हथियारों पर दिए जा रहे प्रोत्साहन का कुछ असर

रिपोर्ट हालांकि यह भी कहती है कि मोदी सरकार के स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के कारण भारत के कुल आयात में हल्की कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2016 से 2020 की तुलना में 2021 से 2025 के बीच हथियार आयात में लगभग चार प्रतिशत की कमी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कमी मुख्य रूप से देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन देने और घरेलू उद्योगों की क्षमता बढ़ाने की नीति का परिणाम है। मोदी सरकार का लक्ष्य दीर्घकाल में विदेशी निर्भरता कम करते हुए आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था स्थापित करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की हथियार आयात में आई कमी का एक कारण यह भी है कि देश अब अपने हथियारों के डिजाइन और निर्माण में अधिक सक्षम हो रहा है। हालांकि घरेलू उत्पादन परियोजनाओं में अक्सर देरी की समस्या भी सामने आती है, फिर भी स्वदेशी क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार की आत्मनिर्भर रक्षा नीति के तहत स्वदेशी युद्धक विमान, मिसाइल प्रणाली, ड्रोन और नौसैनिक उपकरणों के विकास पर तेजी से काम चल रहा है। इससे आने वाले वर्षों में विदेशी हथियारों पर निर्भरता और कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।

पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा हथियार आयातक

पाकिस्तान के लगभग 80 प्रतिशत हथियार चीन से आते हैं। वर्ष 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है, जबकि वर्ष 2016 से 2020 के बीच वह दसवें स्थान पर था। इन दो अवधियों के बीच पाकिस्तान के हथियार आयात में लगभग 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वैश्विक आयात में उसकी हिस्सेदारी लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच वैश्विक हथियार व्यापार में लगभग 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में दुनिया के पांच सबसे बड़े हथियार आयातक यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान रहे, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत रही। वहीं, हथियार निर्यात के मामले में अमेरिका अब भी दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 42 प्रतिशत है। फ्रांस लगभग 9.8 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर और रूस लगभग 6.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है।

मॉस्को की हिस्सेदारी 2011-15 में 70% से घटकर 2021-25 में 40 प्रतिशत

भारत सरकार द्वारा मेक-इन-इंडिया हथियारों पर दिए जा रहे प्रोत्साहन के कारण आयात में मामूली गिरावट के बावजूद, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2021 से 2025 के बीच वैश्विक हिस्सेदारी के 8.2 प्रतिशत के साथ प्रमुख हथियारों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। रिपोर्ट में हथियारों की आपूर्ति के लिए रूस पर नई दिल्ली की दशकों पुरानी निर्भरता में आई भारी गिरावट को भी उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मॉस्को की हिस्सेदारी 2011-15 में 70 प्रतिशत से घटकर 2021-25 में 40 प्रतिशत हो गई है।

फ्रांस और इजराइल की हिस्सेदारी क्रमशः 29% और 15% तक बढ़ गई

फ्रांस और इजराइल को इसका सबसे अधिक लाभ हुआ है, जिनकी हिस्सेदारी क्रमशः 29 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक बढ़ गई है। 2016-2020 के चक्र की तुलना में भारत के हथियार आयात में 4 प्रतिशत की गिरावट स्वदेशी हथियारों पर देश के जोर देने के कारण हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है, यह कमी आंशिक रूप से भारत की अपने हथियारों को डिजाइन करने और उत्पादन करने की बढ़ती क्षमता के कारण है - हालांकि घरेलू उत्पादन में अक्सर काफी देरी होती है।

यूक्रेन 9.7% हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की नई रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 में यूक्रेन 9.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। 2021 से 2025 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2 प्रतिशत रही, हालांकि 2016-2020 की तुलना में इस अवधि में भारत के आयात में 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस अवधि में भारत को सैन्य उपकरणों की सबसे ज्यादा आपूर्ति रूस ने की, लेकिन रूस पर निर्भरता लगातार घट रही है।

भारत की पश्चिमी देशों के साथ कई बड़े रक्षा सौदों की संभावना

पश्चिमी देशों के साथ कई बड़े रक्षा सौदों की संभावना को देखते हुए, भारतीय आयात में यह रुझान आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा। इनमें फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान (जिनकी लागत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये हो सकती है), जर्मनी से छह वायु-स्वतंत्र प्रणोदन (एआईपी) से लैस पारंपरिक पनडुब्बियां, अमेरिका से छह अतिरिक्त पी-8 आई पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान और इजराइल के साथ मिसाइल रक्षा प्रणालियों और ड्रोन पर कई सौदे शामिल हैं। सिप्री की रिपोर्ट में मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत का शस्त्रागार मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न दोहरे खतरे से प्रेरित है। सिप्री विश्लेषक ने कहा, दक्षिण एशिया में, भारत द्वारा हथियारों का भारी मात्रा में आयात मुख्य रूप से चीन से संभावित खतरे और चीन से हथियारों के निर्यात के प्रमुख प्राप्तकर्ता पाकिस्तान के साथ भारत के लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण है। आयातित हथियारों का इस्तेमाल 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में किया गया था, दोनों ही परमाणु-सशस्त्र देश हैं। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भारत की हथियार खरीद मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावित है। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव में आयातित हथियारों का प्रयोग भी किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और पाकिस्तान के साथ उसका घनिष्ठ रक्षा सहयोग भारत के लिए दोहरी चुनौती पैदा करता है। यही कारण है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से आधुनिक बना रहा है।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही महिलाएं

अगर हम इक्कीसवीं सदी की बात करे तो यहां की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही है। अब तो भारत की संसद ने भी महिलाओं के लिये लोकसभा व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पास कर दिया है।

जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज और देश मजबूत होते है। इसलिए पूरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च 1911 से पूरे विश्व में मनाया जाता है। पूरी दुनिया के साथ भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं हैं। भारतीय महिलाएं तो लड़ाई के मैदान में भी कमाल कर रही हैं। आपरेशन सिंदूर में उनकी ताकत दुनिया ने देखी थी। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए मनाया जाता है। अगर हम इक्कीसवीं सदी की बात करे तो यहां की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही है। अब तो भारत की संसद ने भी महिलाओं के लिये लोकसभा व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पास कर दिया है। उससे आने वाले समय में भारत की राजनीति में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जायेगी।

देश में महिलाओं को अब सेना में भी महत्वपूर्ण पदो पर तैनात किया जाने लगा है। जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह जागरूकता बढ़ाने, बाधाओं को तोड़ने और सभी के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने का दिन है। यह समानता और अधिकारों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, जो महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक है। यह एक ऐसा दिन है जो महिलाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम है दान से लाभ है, जो उदारता, सहयोग और सामूहिक प्रगति के मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह अभियान इस बात पर प्रकाश डालता है कि महिलाओं का समर्थन करना और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना सभी के लिए व्यापक सामाजिक और आर्थिक लाभ ला सकता है। इस अभियान का मूल विचार यह है कि जब महिलाएं शिक्षा, नेतृत्व, उद्यमिता, विज्ञान, कला और राजनीति जैसे क्षेत्रों में सशक्त होती हैं, तो इससे मजबूत समुदाय और साझा समृद्धि का निर्माण होता है। सहयोग और समान अवसरों को प्रोत्साहित करके, यह अभियान समाज में समावेशी विकास और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देना चाहता है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

समरसता की चेतना का पोषण दूर करेगा विभाजन

डॉ. रितु सारस्वत

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित नए नियमों को लेकर देशभर में विवाद पूरी तरह थमा नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर शिक्षाविदों, छात्र संगठनों और आम नागरिकों तक, विभिन्न स्तरों पर इस प्रस्ताव का विरोध दिखाई दे रहा है। आलोचकों का मानना है कि इन नियमों से उच्च शिक्षा की स्वायत्तता और शैक्षणिक ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जबकि सरकार और आयोग का तर्क है कि ये बदलाव शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित न रहकर सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है। इस विरोध की तीव्रता का अंदाजा राजधानी दिल्ली में हुए प्रदर्शनों से लगाया जा सकता है। जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और यूजीसी द्वारा प्रस्तावित नियमों का खुलकर विरोध किया।

गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पूर्व में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन्स, 2026' के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर ने व्यापक बहस को उत्पन्न कर दिया। अवांछित तर्कों के बीच हमें एक गंभीर विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव उस रूप में विद्यमान है, जिस रूप में यह प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है? सत्ताईस वर्षों के अध्यापन अनुभव और हजारों विद्यार्थियों के निकट संपर्क के आधार पर मेरा अनुभव रहा है कि महाविद्यालयीन परिसर जातिगत भेदभाव से मुक्त सामाजिक संरचना का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वहां का वातावरण मूलत: संवाद, सहभागिता और मित्रता के आधार पर विकसित होता है, जहां पारस्परिक संबंध जातिगत पहचान के बजाय मानवीय संपर्क और साझा शैक्षणिक जीवन से निर्मित होते हैं।

दुर्भाग्य यह है कि भारतीय समाज आज जातिगत विमर्श के ऐसे जाल में उलझता जा रहा है, जहां पूर्व धारणाएं प्राय: तथ्यों पर भारी पड़ती प्रतीत होती हैं। हम वास्तविकताओं की शांत और गहन पड़ताल करने के बजाय प्रचलित मान्यताओं को ही अंतिम सत्य मान लेने की प्रवृत्ति विकसित कर चुके हैं। यह भी एक व्यापक धारणा बन गई है कि

भारतीय परंपराएं स्वयं जातिगत भेदभाव का पोषण करती रही हैं परंतु क्या यह सत्य है? या ऐसा कुछ है जिससे हम परिचित नहीं हैं। एएल बाशम ने 1954 में 'द वन्डर दैट वाज इण्डिया' में लिखा था कि 'मध्य युग के पूर्व भारत में जाति व्यवस्था सरल थी।' बहुत से उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जहां वर्ग परिवर्तित होता रहा है। कार्य को बदलने पर सामाजिक स्थिति बदलती रहती है। वैदिक वाङ्मय और प्राचीन संस्कृत साहित्य में कहीं भी जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता के उदाहरण परिलक्षित नहीं होते हैं। शूद्र' शब्द को 'क्षुद्र' से बना हुआ मानना भाषाशास्त्रीय रूप से प्रामाणित नहीं है। इसकी व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, अत: इसे सीधे 'हीन' अर्थ से जोड़ना उचित प्रतीत नहीं होता। अथर्ववेद के शब्दों की निरुक्ति में अपने श्रम के स्वेद (पसीने) से विविध उत्पादकीय कार्य में रत वर्ग को शूद्र कहा गया है। अर्थात परिश्रमपूर्वक विविध प्रकार की मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन में रत (संलग्न) रहने वाले वर्ग को शूद्र कहकर संबोधित किया गया। इसमें किंचित भी संशय नहीं कि भारत पर हुए बाहरी आक्रमणों से पूर्व अपने उत्पादन कार्यों के प्रतिफल के स्वरूप शूद्र का समाज में आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च स्थान था। इसलिए कामन्दक नीतिसार में कहा गया है कि राजा को नया नगर बसाते समय शूद्र जो कि विभिन्न मूल्यवान वस्तुएं उत्पादित करते हैं उन्हें व वैश्य जो उन वस्तुओं के व्यापार से आय उत्पन्न करके राजस्व बढ़ाते हैं उन्हें अधिक संख्या में बसाना चाहिए। एगंस मेड्सिन ने अपने अध्ययन में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि विश्व का एक-तिहाई उत्पादन भारत में होने व प्राचीन वाङ्मय के अनुसार समग्र उत्पादन का दायित्व शूद्रों के नियंत्रण में होने से ही शूद्र प्राचीन काल से ही राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार रहे हैं।

ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि यकायक शूद्र निम्न श्रेणी में कैसे अवस्थित हो गए? अगर इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह विदित होगा कि इस वर्ग के पास कौशल और परिश्रम की निधि थी जिसे औद्योगीकरण के प्रभाव ने समाप्त कर दिया और परिणामस्वरूप रोजगार का अभाव उनकी आर्थिक विपन्नता का कारण बना। अंग्रेजों द्वारा उन्हें यह विश्वास निरंतर दिलाया गया कि उनके साथ जो कुछ भी नकारात्मक हुआ है और हो रहा है उसका कारण श्रेष्ठी वर्ग हैं।

'साइलेंट किलर' बन सकता है बढ़ता तापमान

भीषण गर्मी से स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे हो सकते हैं, जैसे अंगों की क्रियाशीलता बाधित होना, विकलांगता आदि। साथ ही हृदयघात भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा, कृषि, उत्पादकता व जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे 'साइलेंट किलर' की संज्ञा दी है।

ज्ञानेंद्र रावत

दुनिया में बढ़ती गर्मी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि साल 2050 तक, दुनिया के लगभग 41 फीसदी लोग खतरनाक स्तर पर भीषण गर्मी का सामना करने को विवश होंगे। साल 2010 तक यह आंकड़ा महज 23 फीसदी था। यह स्थिति तब होगी जब दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक युग से दो डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे। सच तो यह है कि भीषण गर्मी से स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे हो सकते हैं, जैसे अंगों की क्रियाशीलता बाधित होना, विकलांगता, चक्कर, सिरदर्द आदि, साथ ही हृदयघात भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा, कृषि, उत्पादकता, जीवन और विस्थापन पर भी खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे 'साइलेंट किलर' की संज्ञा दी है। वर्ष 2026 की शुरुआत में ही गर्मी, सूखा और आग की घटनाओं ने चेतावनी दे दी है।

यह बदलाव भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक गंभीर संकेत है, क्योंकि भारत की विशाल आबादी और पहले से ही गर्म जलवायु इसे और अधिक संवेदनशील बना देती है। इसका मुख्य कारण 1950 के बाद से लू या हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि है। कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण विकासशील देशों में आर्थिक रूप से कमजोर लोग गर्मी और स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन के अनुसार, भारत में गर्मी के कारण उत्पादकता में भारी कमी आएगी और जीडीपी में गिरावट होने की आशंका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका, चीन और भारत में 23 से 30 अतिरिक्त दिन गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया के शोधों ने यह साबित कर दिया है कि भीषण गर्मी से प्रभावित देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर है। भारत के आधे से अधिक जिले भीषण गर्मी का सामना करेंगे।

यह निष्कर्ष 'नेचर सस्टेनेबिलिटी' जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट और 'हाउ एक्सट्रीम हीट इज इम्पैक्टिंग इंडिया असेसमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल हीट रिस्क-2025' के नाम से सीईईडब्ल्यू के अध्ययन में सामने आया है। इस अध्ययन में सबसे गर्म रातों, यानी 'हॉट नाइट्स', की तादाद में वृद्धि का उल्लेख किया गया है, जिससे हृदय रोग और उससे जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक और हृदयाघात की संभावना भी अधिक रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, गर्मी का यह असर 1.5 डिग्री की सीमा पार करने से पहले ही दिखने लगेगा। अगले 5 वर्षों में लाखों घरों और दफ्तरों को कूलिंग सिस्टम की जरूरत में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। इसके परिणामस्वरूप, जहां ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, वहीं कार्बन उत्सर्जन में भी इजाफा होगा।

गौरतलब है कि आज हम गर्मी के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करते हुए पर्यावरण में वृक्षों की महत्ता को नकार रहे हैं। दुख की बात यह है कि विकास के नाम पर हम हर साल लाखों हरे-भरे पेड़ों की बलि दे रहे हैं। यह सिलसिला पूरे देश में बेरोकटोक जारी है, और सरकार मौन है। राजस्थान में ग्रीन एनर्जी के नाम पर हजारों-लाखों खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष के अनुसार, खेजड़ी की कटाई के कारण इस क्षेत्र का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। सीईईडब्ल्यू के अनुसार, देश में गर्मी के सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। देश के 417 जिले उच्च जोखिम की श्रेणी में हैं, जबकि 201 जिले मध्यम जोखिम का सामना कर रहे हैं। अब उत्तर भारत के शुष्क क्षेत्रों में भी तटीय इलाकों की उमस बढ़ रही है और सिंधु और गांगेय क्षेत्रों में पिछले दशक के मुकाबले आर्द्रता में 10 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, जयपुर जैसे शहरों में आर्द्रता का स्तर 40-50 फीसदी तक पहुंच चुका है।

चिंताजनक पहलू यह है कि बढ़ती गर्मी का खतरा सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और केरल जैसे ग्रामीण इलाके भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। खुले आकाश के नीचे काम करने वाले खेतिहर मजदूरों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। यूएनईएससीएपी का कहना है कि इन मजदूरों में हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और गर्मी से संबंधित बीमारियां अधिक होती हैं, क्योंकि छाया, पानी और आराम की कमी स्थिति को और गंभीर बना देती है। उन्हें समय पर इलाज भी नहीं मिल पाता। संयुक्त राष्ट्र ने जोर दिया है कि बढ़ती गर्मी से बचाव के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए मौसम और जलवायु जोखिम की सटीक जानकारी को निर्णय प्रणालियों और अर्ली वार्निंग सिस्टम में शामिल करना होगा। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय और इस दिशा में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना जरूरी है। यह महज एक चुनौती नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का सवाल भी है।

घर पर बनाएं वेज आमलेट

अंडे का आमलेट तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने वेज आमलेट ट्राई किया है? दरअसल, आजकल हेल्दी और वेजिटेरियन फूड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में वेज आमलेट उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो अंडा नहीं खाते लेकिन आमलेट जैसा स्वाद और टेक्सचर चाहते हैं। ये रेसिपी न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद मानी जाती है। वेज आमलेट को बेसन, सब्जियों और हल्के मसालों से तैयार किया जाता है, जो शरीर को प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। अगर आप कुछ नया, टेस्टी और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो वेज आमलेट जरूर बनाएं।

विधि

वेज आमलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक गहरा बाउल लें और उसमें बेसन डालें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए अच्छी तरह फेंटें ताकि घोल में कोई गांठ न रहे। घोल न ज्यादा पतला हो और न ज्यादा गाढ़ा, बल्कि आमलेट जैसा स्मूद होना चाहिए। अब इस घोल में बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें। इसके बाद नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन मिलाएं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें ताकि सब्जियां और मसाले बराबर मिल जाएं। इसके बाद एक तवा मध्यम आंच पर गरम करें और उस पर थोड़ा सा तेल डालकर चारों तरफ फैला दें। जब तवा अच्छी तरह गरम हो जाए, तो तैयार घोल को तवे के बीच में डालें और चम्मच से हल्के हाथ से फैलाएं। आमलेट को धीमी आंच पर लगभग 2 से 3 मिनट तक पकने दें। जब नीचे की सतह सुनहरी हो जाए, तब इसे सावधानी से पलटें और दूसरी तरफ भी अच्छे से सेंक लें। दोनों तरफ से पक जाने पर गैस बंद कर दें।

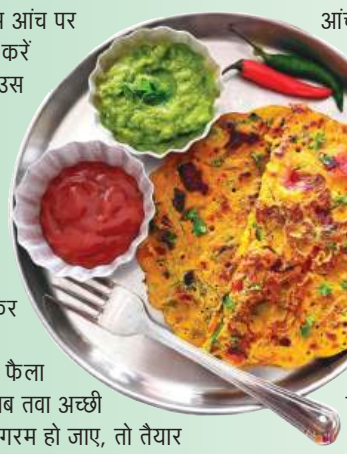

सामान

बेसन- 1 कप, बारीक कटा प्याज- 1, बारीक कटी शिमला मिर्च - 1/2, टमाटर- 1, हरी मिर्च - 1, हरा धनिया - 2 चम्मच, नमक- स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर- 1/2 चम्मच, हल्दी - चुटकी भर, अजवाइन - 1/4 चम्मच, पानी - आवश्यकता अनुसार, तेल - सेकने के लिए।

मिनटों में केले से तैयार करें डेजर्ट

आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में झटपट बनने वाली रेसिपीज की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर आपका भी अचानक मीठा खाने का मन हो और रसोई में ज्यादा समय व्यतीत करने का मन न हो तो आर संडे के दिन केले से कुछ खास बनाकर तैयार करें। केला न सिर्फ तुरंत एनर्जी देता है, बल्कि इससे मिनटों में बनने वाले डेजर्ट भी बेहद स्वादिष्ट होते हैं। खास बात ये है कि केले से बनने वाले इस डेजर्ट के लिए न तो ओवन की जरूरत होती है और न ही किसी भारी तैयारी की। घर में मौजूद कुछ बेसिक चीजों के साथ आप ऐसा डेजर्ट बना सकते हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आए।

सामग्री

पके हुए केले-2 पीस, कंडेंस्ड मिल्क- 2 टेबलस्पून, शहद- एक चम्मच, फ्रेश क्रीम-1/2 कप, इलाइची पाउडर, कटी हुई मेवा।

विधि

इस डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले 2 अच्छी तरह पके केले लें। उनका छिलका उतारकर एक गहरे बाउल में डालें। अब कांटे या मैशर की मदद से केले को पूरी तरह स्मूद मैश कर लें, ताकि उसमें गुठलियां न रहें। अब मैश किए हुए केले में 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क डालें। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। हेल्दी ऑप्शन के लिए शहद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें 1/2 कप फ्रेश क्रीम या अच्छी तरह फेंटा हुआ गाढ़ा दही डालें। इससे डेज़र्ट क्रीमी और सॉफ्ट बनेगा। इसमें चुटकी भर इलायची पाउडर डालें और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं। ऊपर से कटे हुए बादाम, काजू या किशमिश डालें। चाहें तो चॉकलेट चिप्स या बिस्कुट को महीन पीसकर भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। मिश्रण को 5-10 मिनट फ्रिज में रखें और फिर ठंडा-ठंडा सर्व करें। सर्दी के मौसम में जिन लोगों को आइसक्रीम खाना पसंद है, उनके लिए ये डेजर्ट काफी सही विकल्प है। इसे आप बनाकर टंडा-ठंडा ही परोसें, तभी इसका स्वाद अच्छा और मजेदार आएगा।

हंसना मना है

पप्पू- मेरे बाप के आगे बड़े-बड़े लोग कटोरी लेके खड़े होते है, लड़की- अच्छा! कौन है तुम्हारा बाप? पप्पू- पानी पूरीवाला।

पप्पु बहूत देर से एक लड़की को घुर रहा था, लड़की- तेरे घर में मां बहन नहीं है क्या? पप्पु - है न तभी तो देख रहा हूं, क्योंकि मां को बहू और बहन को भाभी चाहिए।

खैरियत पूछने का जमाना गया साहिब, आदमी ऑनलाइन दिख जाये तो समझ लेना सब ठीक है.. भगवान हम सबको ऑनलाइन रखे।

जरुरत से ज़्यादा भगवान को याद मत किया करो क्योंकि, किसी दिन भगवान ने याद कर लिया तो लेने के देने पड़ जायेंगे।

शराबी- अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। शराबी की पत्नी- अरे, पहले अपना पाजामा तो बदल ले करम जले, सुबह से मेरी सलवार पहन कर घूम रहा है...

कहानी — दानवीर कर्ण

महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का जिक्र है। उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। श्रीकृष्ण हमेशा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। वहीं, अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान-पुण्य करते रहते थे, लेकिन श्रीकृष्ण कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। एक दिन अर्जुन ने श्रीकृष्ण से इसका कारण पूछा। श्रीकृष्ण बोले, समय आने पर वह यह साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण है। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। उसने बताया कि पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके दाह संस्कार के लिए उन्हें चन्दन की लकड़ियों की जरूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष से चन्दन की लकड़ियों का इंतजाम किया जाए, लेकिन उस दिन न तो राजकोष में चंदन की लकड़ियां मिली और न ही पूरे राज्य में। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम नहीं कर सका। श्रीकृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आपको एक जगह चंदन की लकड़ियां जरूर मिलेगी, आप मेरे साथ चलिए। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। श्रीकृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुंचे। वहां भी ब्राह्मण ने कर्ण से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। कर्ण ने अपनी मंत्री से चंदन की लकड़ी का इंतजाम करने को कहा। थोड़े समय बाद कर्ण के मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इस पर कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसके महल में चंदन के खंभे हैं, उन्हें तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया जाए। मंत्री ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ी लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो तुम्हारे महल के खंभों में भी चन्दन की लकड़ी लगी है, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया। वहीं, कर्ण ने एक बार फिर अपनी दानवीरता का परिचय दिया।

7 अंतर खोजें

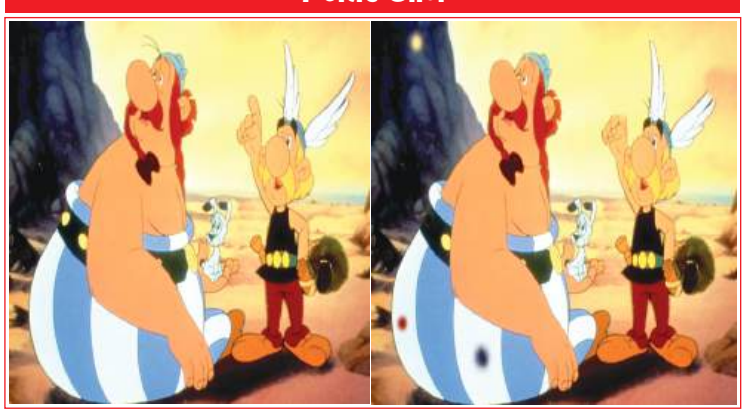

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है। अज्ञात भय सताएगा। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। कुसंगति से बचें। चिंता रहेगी।

वृषभ शुभ समय। भूमि व भवन संबंधी खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। आर्थिक उन्नति होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

मिथुन किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। कारोबार में बुद्धिबल से उन्नति होगी।

कर्क लेन-देन में जल्दबाजी न करें। पुराना रोग उभर सकता है। दु:खद समाचार की प्राप्ति संभव है। किसी के उकसाने में न आएं। बात बिगड़ सकती है। प्रमाद से बचें।

सिंह पराक्रम व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। आय में वृद्धि होगी। कारोबार का विस्तार होगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। प्रयास सफल रहेंगे।

कन्या आय में वृद्धि होगी। कारोबार लाभप्रद रहेगा। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। दूर से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। घर में अतिथियों का आगमन होगा। व्यय बढ़ेगा।

तुला प्रेम-प्रसंग में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। सट्टे व लॉटरी से दूर रहें। कारोबार का विस्तार होगा।

वृश्चिक राजभय रहेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। लेन-देन में जल्दबाजी हानि देगी। शारीरिक कष्ट संभव है। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। व्यवस्था में मुश्किल होगी।

धनु व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नेत्र पीड़ा हो सकती है। मानसिक बेचैनी रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

मकर राज्य से प्रसन्नता रहेगी। कोई बड़ा काम हो सकता है। नई योजना बनेगी। नया उपक्रम प्रारंभ हो सकता है। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा।

कुम्भ आंखों को चोट व रोग से बचाएं। धन प्राप्ति सुगम होगी। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबार लाभदायक रहेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। पूजा-पाठ में मन लगेगा।

मीन पुराना रोग उभर सकता है। अनहोनी की आशंका रहेगी। मातहतों से कहासुनी हो सकती है। पार्टनरों से मतभेद संभव है। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें।

बॉलीवुड | मन की बात

सीआईडी सीरियल छोड़ने को मुझे मजबूर किया गया : जसवीर कौर

जसवीर कौर इस समय टीवी शो अनुपमा में नजर आ रही हैं। उन्होंने सुबोजीत घोष के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में सीआईडी शो के बारे में खुलकर बात की। जसवीर कौर ने बताया कि करीब दो साल तक काम करने के बाद उन्हें अचानक पॉपुलर क्राइम शो सीआईडी छोड़ने के लिए कह दिया गया था। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय तक लगातार इस शो की शूटिंग कर रही थीं, लेकिन फिर अचानक उन्हें बताया गया कि उनका किरदार खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'लगभग दो साल हो गए थे। हर शुक्रवार, हर शनिवार शूटिंग होती थी। लगातार शूट करना पड़ता था, रोज शूटिंग, कभी-कभी 31 दिनों तक भी। कई बार मैं कहती थी कि कल छुट्टी दे दो।'जसवीर ने बताया कि काम काफी ज्यादा था, लेकिन टीम कभी-कभी उनकी छुट्टी की मांग भी मान लेती थी। हालांकि, एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा, 'अचानक ऑफिस में बताया गया कि आपको शो छोड़ना होगा।' अपने जीवन के उस दौर को याद करते हुए जसवीर ने कहा कि वह उनके करियर का सबसे कठिन समय था। उस दौरान उन्हें कई वर्षों तक आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा और वह बस किसी तरह हर दिन निकालने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने कहा, '7 साल तक मैंने सिर्फ सर्वाइवल किया। मैंने घर भी ले लिया था। मैं जमीन पर बैठकर रोती थी। मुझे पता था मैं कौन हूं, लेकिन कल क्या होगा यह नहीं पता था। मेरे पास 100 रुपये भी नहीं होते थे और 800 रुपये टैक्स देना पड़ता था।'जसवीर कौर अपने करियर में कई टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं, जिनमें गंगा, इश्क का रंग सफेद, द एडवेंचर्स ऑफ हातिम और घर की लक्ष्मी बेटियां जैसे शो शामिल हैं। वह साल 2020 से अनुपमा का हिस्सा हैं।

कोर्ट ने अभिनेत्री श्वेता मेनन को अश्लीलता के केस से किया बरी

बॉलीवुड | गपशप

केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को मलयालम फिल्म एक्ट्रेस श्वेता मेनन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी कुछ पुरानी फिल्मों और विज्ञापनों के अश्लील सीन प्रकाशित या प्रसारित किए थे। जस्टिस सी.एस. डियास ने एक्ट्रेस की उस याचिका को मंजूर कर लिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में इस एफआईआर से जुड़ी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एक्ट्रेस की इस दलील में दम है कि शिकायत को जांच के लिए भेजने से पहले जांच करने की जरूरी शर्तों का पालन किया जाना चाहिए था।

जब यह एफआईआर दर्ज की गई थी, तब मेनन एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (स्क्रू) में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही थीं। बाद में उन्हें स्क्रू का अध्यक्ष चुन लिया गया। शिकायतकर्ता, मार्टिन मेनाचेरी ने आरोप लगाया था कि वर्षों पहले अभिनेत्री एक कंडोम के विज्ञापन में नजर आईं। वह पलेरी माणिक्यम, रतिनिर्वेदम और कलिमान्नु जैसी फिल्मों में अभिनय करके कथित तौर पर अश्लील तरीके से पेश आईं।

अपनी याचिका में, एक्ट्रेस ने दावा किया था कि उन पर लगाए गए आरोप बदनीयती से प्रेरित हैं। जिन अपराधों के लिए उन पर केस दर्ज किया गया है, वे बनते ही नहीं हैं। उन्होंने दलील दी कि शिकायत में जिन फिल्मों का जिक्र किया गया है, वे विधिवत सेंसर और प्रमाणित थीं। पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

कलाकारों की एक झलक पाने के लिए उत्साहित हुए फैंस, हर्षवर्धन राणे को रोकनी पड़ी फोर्स 3 की शूटिंग

हर्षवर्धन राणे अपनी अपकमिंग फिल्म फोर्स 3 को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग गुजरात में शुरू हुई है। फोर्स फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की शूटिंग पूजा के साथ शुरू हुई। हाल ही में शूटिंग में तब रुकावट आ गई, जब कलाकारों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक शूटिंग स्थल पर जमा हो गए। इससे प्रोडक्शन टीम को दिक्कत हुई और हर्षवर्धन राणे को आगे आना पड़ा।

फोर्स 3 के शूटिंग स्थल पर जब ज्यादा फैंस जमा हो गए तो हालात बेकाबू हो गए। इस वजह से शूटिंग रोक देनी पड़ी। ऐसे में हर्षवर्धन राणे को आगे आना पड़ा। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि हर्षवर्धन राणे उत्साहित फैंस को शांत करने के लिए आगे बढ़े। हाथ जोड़कर, एक्टर ने भीड़ से गुजारिश की कि वे अपनी आवाज धीमी रखें और टीम के साथ सहयोग करें, ताकि शूटिंग बिना किसी रुकावट के जारी रहे। उनकी अपील के तुरंत बाद, भीड़ शांत हो गई, जिससे प्रोडक्शन टीम अपना काम फिर से शुरू कर पाई।

इसके बाद हर्षवर्धन राणे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने शूटिंग में हुई दिक्कत के लिए क्रू से माफी मांगी। उन्होंने कैप्शन में लिखा गुजरात में फोर्स 3 की शूटिंग हो रही है। साउंड डिपार्टमेंट, डायरेक्शन टीम और प्रोडक्शन टीम से माफी चाहता हूं। कब रिलीज होगी फिल्म?

फोर्स 3 का निर्देशन भव धूलिया कर रहे हैं। इसके लेखक सीमाब हाशमी हैं। इसमें जॉन अब्राहम एसीपी यशवर्धन सिंह के अपने किरदार में एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर तान्या मानिकतला को लिया गया है। इसका प्रोडक्शन 2026 की शुरुआत में शुरू हुआ था। माना जा रहा है कि यह फिल्म 2027 तक सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी।

अजब-गजब | इस देश की इस परंपरा को देख लोग हैं हैरान

यहां शादी से पहले पूछे जाते हैं सात पीढ़ियों के नाम, पता न होने पर शादी हो जाती है कैंसिल

दुनिया के अलग-अलग देशों में शादी से जुड़ी कई अनोखी परंपराएं देखने को मिलती हैं। लेकिन कजाकिस्तान की एक परंपरा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इस परंपरा के बारे में जानकर लोग हैरान रह जा रहे हैं। दरअसल, कजाकिस्तान में शादी से पहले लड़का और लड़की की कुंडली नहीं मिलाई जाती। यहां शादी तय करने से पहले उनसे उनकी पिछली सात पीढ़ियों के पूर्वजों के नाम पूछे जाते हैं। अगर कोई अपनी सात पीढ़ियों का सही-सही हिसाब नहीं बता पाता, तो शादी में परेशानी खड़ी हो सकती है।

कजाख समाज में यह परंपरा काफी पुरानी मानी जाती है। यहां यह विश्वास किया जाता है कि अगर लड़का और लड़की की सात पीढ़ियों के अंदर कोई एक समान पूर्वज निकल आता है, तो दोनों को रिश्ते में भाई-बहन माना जाता है। ऐसे में उनकी शादी नहीं हो सकती। इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी को रोकना है। ऐसा करने से आने वाली पीढ़ियों में जेनेटिक बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। इसलिए यहां शादी से पहले वंशावली की पूरी जांच की जाती है। कजाकिस्तान की शादी की परंपराएं यहीं खत्म नहीं होतीं। यहां एक और दिलचस्प रिवाज भी है, जिसे 'अलाकाचू' कहा जाता है। इसमें लड़का अपनी होने वाली दुल्हन को 'किडनैप' करके ले जाता है। हालांकि यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह लड़की की सहमति से ही किया जाता है। खासकर तब, जब कपल के पास शादी का भारी खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। कजाकिस्तान की संस्कृति में दहेज का तरीका भी भारत से बिल्कुल अलग है। यहां दूल्हा दहेज लेता नहीं, बल्कि देता है। दूल्हा, दुल्हन के परिवार को पैसे या उपहार देता है। इसे 'खलीम' कहा जाता है और इसे दूल्हे की आर्थिक क्षमता और लड़की के परिवार के प्रति सम्मान के रूप में देखा जाता है।

जैसे ही कजाकिस्तान की इस अनोखी परंपरा की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दीं। कई यूजर्स ने इसकी तुलना भारत के कुछ राज्यों की पुरानी परंपराओं से भी की। कुछ लोगों का कहना है कि विज्ञान और परंपरा का ऐसा मेल वाकई दिलचस्प है। वहीं कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर यह नियम हर जगह लागू हो जाए, तो कई लोगों को अपने पूर्वजों के बारे में काफी कुछ याद करना पड़ेगा।

एलपीजी किल्लत के बीच इंडक्शन बना बैकअप, अचानक बढ़ गई डिमांड

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर कई तरह की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि कई जगहों पर सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे या उन्हें ब्लैक में बेचा जा रहा है। इन खबरों के सामने आने के बाद कई उपभोक्ता चिंतित नजर आ रहे हैं और रसोई के लिए वैकल्पिक विकल्प तलाशने लगे हैं। इन खबरों का असर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रहा है। कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के ट्रेंड्स में इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक चूल्हे की सर्च अचानक बढ़ गई है। लोग 'इंडक्शन स्टोव', 'इलेक्ट्रिक कुकटॉप' और 'गैस का विकल्प' जैसे शब्द तेजी से सर्च कर रहे हैं। कई ग्राहक अब एहतियात के तौर पर इंडक्शन कुकटॉप खरीद रहे हैं, ताकि अगर कभी गैस सिलेंडर मिलने में देरी हो जाए तो खाना बनाने में परेशानी न हो। दरअसल, अधिकांश घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी कारणवश सिलेंडर की सप्लाई देर से मिले तो किचन का काम प्रभावित हो सकता है। ऐसे में लोग बैकअप के तौर पर इंडक्शन कुकटॉप खरीदना बेहतर विकल्प मान रहे हैं। इंडक्शन बिजली से चलता है और इसमें गैस की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि यह गैस के विकल्प के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी कई लोग यह सलाह लेते नजर आ रहे हैं कि गैस की जगह इंडक्शन या इलेक्ट्रिक कुकटॉप का इस्तेमाल कितना सही रहेगा। हालांकि गैस कंपनियों और सरकारी एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। अधिकारियों के अनुसार देश में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी कमी की स्थिति नहीं है। सरकार ने लोगों से कहा है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और सिलेंडर की बुकिंग केवल आधिकारिक माध्यमों से ही करें। साथ ही अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर का स्टॉक जमा करने से भी बचने की सलाह दी गई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण कुछ जगहों पर एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता देखी जा रही है। खासकर दिल्ली में कई रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस से जुड़े लोग सतर्क हो गए हैं।

चुनी सरकार के पास पूरे अधिकार नहीं

पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला बोले- राज्य का दर्जा बहाल हो

» बोले- भारत की ताकत उसके धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र में है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि वहां चुनी हुई सरकार तो है, लेकिन उसके पास वे अधिकार नहीं हैं जो होने चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राज्य का दर्जा न होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री पर हुए हमले से जोड़ने संबंधी सवाल पर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव इस आश्वासन के साथ कराए गए थे कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि चुनी हुई सरकार है, लेकिन उसके पास आवश्यक अधिकार नहीं हैं। चुनाव इस वादे के साथ हुए थे कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और लोगों की समस्याएं दूर की जाएंगी।

कई साल बीत गए वह राज्य का दर्जा कहां है? अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों के सामने दिया गया था। जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा न होने के कारण अपराध बढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपराध पूरे देश में होते हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ती गरीबी और वैश्विक हालात से आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश में हर जगह अपराध होते हैं। गरीबी बढ़ रही है और वैश्विक स्थिति, खासकर ईरान से जुड़े युद्ध के कारण, हमें भी प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से सबसे ज्यादा परेशानी मध्यम वर्ग को होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई साजिश है तो उसे सामने आना चाहिए। लेकिन मैं केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से निवेदन करता हूं कि जब वे बार-बार कहते हैं कि स्थिति पूरी तरह सुधर गई है, तो यह भी देखें कि क्या माहौल वास्तव में इतना सुरक्षित हो गया है कि हम सम्मान के साथ स्वतंत्र रूप से घूम सकें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को जमानत दिए जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को देश को बेहतर बनाने के लिए आगे आना चाहिए। लोग आगे आएं और इस देश को बेहतर बनाने में मदद करें, ताकि यहां लोग सम्मान और मानवता के साथ रह सकें। हमें नफरत छोड़नी होगी। कश्मीरी पंडितों के लंबे समय से विस्थापन का जिक्र करते हुए उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और मेल-मिलाप की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू भाई अब भी अपने घरों से दूर रह रहे हैं। यह कब तक चलेगा? 34 साल हो गए हैं। अब समय आ गया है कि हम साथ मिलकर रहें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं और भारत की ताकत उसके धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र में है। अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन भारत एक स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।

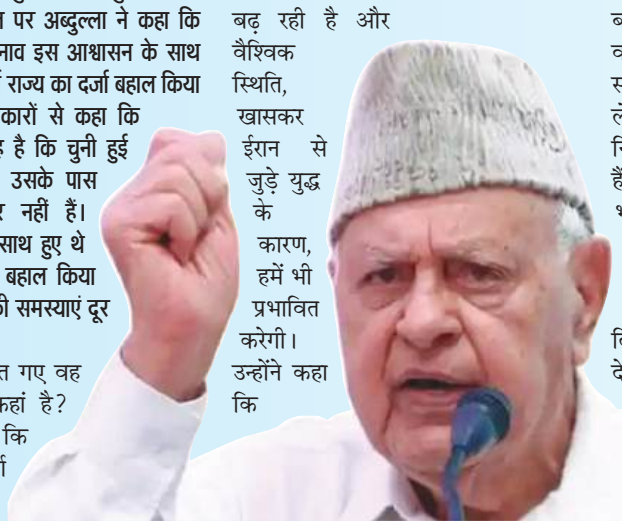

फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

जम्मू कश्मीर में क्रिकेट संघ से जुड़े बहु करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले के मामले में श्रीनगर की एक अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मौजूद जानकारी के अनुसार यह आदेश उस समय जारी किया गया जब आरोप तय करने की सुनवाई के दौरान फारूक अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने इस मामले में पहले 12 मार्च की तारीख तय की थी, जिस दिन आरोप तय किए जाने थे। बता दें कि इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने वर्ष 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया था। हालांकि उसके बाद से अब तक आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी होती रही और मुकदमे की औपचारिक सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि फारूक पहले भी इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में उनका नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।

जब पूर्व सीएम सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या : सुरिंदर चौधरी

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले के बाद केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और सवाल किया कि अगर इतने प्रभावशाली नेता को निशाना बनाया जा सकता है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। एएनआई से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि असंबंधित मुद्दों पर राजनीतिक बहस में उलझने के बजाय, हमले के कारणों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। चौधरी ने कहा कि आज लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इधर-उधर की बातें करने के बजाय, उन्हें यह बताना चाहिए कि यह हमला क्यों हुआ। अगर फारूक जैसे उच्च सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति पर हमला हो सकता है, तो आम आदमी की क्या हालत होगी? गुरुवार को फारूक ने घटना का ब्यौरा देते हुए केंद्र से जम्मू-कश्मीर की स्थिति सुधारने पर ध्यान देने का आग्रह किया।

सनराइजर्स लीड्स ने पाक खिलाड़ी पर लगाया दांव

» आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का बहिष्कार करने की मांग तेज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लंदन। इंग्लैंड की फ्रेंचाइजी लीग द हंड्रेड के 2026 सीजन के लिए गुरुवार को खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इस दौरान भारतीय स्वामित्व वाली सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के अबरार अहमद पर दांव लगाया और उन्हें 2.34 करोड़ रुपये में खरीदा। सनराइजर्स फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक सन ग्रूप के पास है जिसके मालिक कलानिथी मारन हैं। फ्रेंचाइजी की सीईओ और ग्रूप का प्रसिद्ध चेहरा काव्या मारन भी इस दौरान नीलामी टेबल पर मौजूद रहीं।

काव्या टीम के मुख्य कोच डेनिल विटोरी के साथ लंदन में मौजूद रहीं जब सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को खरीदने के लिए बोली लगाई। सनराइजर्स लीड्स के कप्तान हैरी ब्रूक हैं। पिछले कई वर्षों में यह पहली बार है जब आईपीएल से जुड़ी किसी फ्रेंचाइजी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा है। मालूम हो कि आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हिस्सा लेती है जिसका स्वामित्व सन ग्रूप के पास ही है। जिसके चलते आईपीएल की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन विवादों में घिर गई हैं और आईपीएल में सनराइजर्स का बहिष्कार करने की मांग सोशल मीडिया पर तेज हो गई है। यूजर्स सोशल मीडिया पर काव्या मारन की आलोचना कर रहे हैं और आईपीएल के आगामी सीजन में उनकी टीम का समर्थन नहीं करने की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स पाकिस्तान के खिलाड़ी अबरार अहमद को द हंड्रेड टूर्नामेंट के लिए सनराइजर्स लीड्स टीम में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं।

श्रीलंका दौरे पर टी20 सीरीज भी खेल सकता है भारत

नई दिल्ली। टी20 विश्वकप की चैंपियन भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर टी20 सीरीज भी खेल सकती है। अगले 12 महीने में व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बावजूद भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेल सकती है। प्रस्तावित मैच निर्धारित द्विपक्षीय दौरे और टूर्नामेंट्स के साथ ही होंगे। बीसीसीआई श्रीलंका दौरे के दौरान तीन टी20 सीरीज भी खेलने का प्लान बनाने पर विचार कर रही है। ये टी20 सीरीज दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले होंगे जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) का हिस्सा है। टेस्ट सीरीज जुलाई-अगस्त में होनी है। दरअसल, टी20 सीरीज खेलना श्रीलंका क्रिकेट की ओर से प्रस्तावित है। श्रीलंका क्रिकेट ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए फंड जुटाने की योजना से इस टी20 सीरीज का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल नवंबर में श्रीलंका में दितवाह तूफान आया था जिस कारण कई क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था।

गैस संकट और महंगाई पर केंद्र के खिलाफ टीएमसी का हल्ला बोल

» सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में विरोध मार्च निकालने का किया ऐलान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में रसोई गैस और वाहन गैस की कमी को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है और इसी बीच ममता बनर्जी ने कोलकाता में विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। यह मार्च सोमवार को कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर एस्प्लानेड के डोरिना क्रॉसिंग तक निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल होंगे। बता दें कि इस मार्च का उद्देश्य रसोई गैस और वाहन गैस की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के खिलाफ विरोध दर्ज कराना बताया जा रहा है।

पार्टी की ओर से जारी पोस्टर में कहा गया है कि आम लोगों को गैस की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और आपूर्ति से जुड़े फैसलों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल के कई इलाकों में गैस सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ गई है। राज्य सरकार के अनुसार कुछ ही दिनों में सिलेंडर बुकिंग की संख्या दो लाख से बढ़कर करीब छह लाख तक पहुंच गई है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। बनर्जी ने भी हाल ही में राज्य के अधिकारियों और तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपात बैठक की थी।

जल संसाधन विभाग में टेंडर सिंडिकेट, फर्जी बैंक गारंटी का खेल चल रहा : पटवारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जल संसाधन विभाग की टेंडर प्रक्रिया और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने कहा कि विभाग में टेंडर सिंडिकेट, फर्जी बैंक गारंटी और ठेकेदारी नेटवर्क का खेल चल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को आवेदन देगी।

पटवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस साल को कृषि वर्ष घोषित किया है, लेकिन जमीन पर हालात इसके विपरीत हैं। कई सिंचाई परियोजनाएं ठप पड़ी हैं और किसान पानी के लिए परेशान हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सिंचाई परियोजनाएं ही नहीं चल रहीं, तो इसे कृषि वर्ष कैसे कहा जा सकता है।

तमिलनाडु में एनडीए सत्ता में आएगी: दिनाकरन

» एएमएमके के महासचिव बोले -जनता डीएमके सरकार से असंतुष्ट है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने कहा है कि तमिलनाडु में एनडीए सत्ता में आएगा, क्योंकि जनता मौजूदा सरकार से असंतुष्ट है। दिनाकरन ने सत्तारूढ़ डीएमके की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी हर किसी को अपने गठबंधन में शामिल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के कार्यकाल में उच्च पदों पर रहे कई नेता, जो अब राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो चुके हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद डीएमके गठबंधन में शामिल किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि डीएमके का दावा है कि वह अपने गठबंधन सहयोगियों के कारण मजबूत है और इसी मजबूती के कारण उसने पिछले चुनाव जीते थे। हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पार्टी पहले से ही मजबूत है तो उसे गठबंधन में और पार्टियों को शामिल करने की क्या जरूरत है। इसका कारण मौजूदा सरकार के प्रति जनता में बढ़ती असंतुष्टि है। दिनाकरन ने कहा कि 2011 के चुनावों से पहले, चुनाव परिणाम घोषित होने तक जनता की असंतुष्टि दिखाई नहीं दी थी। उन्होंने आगे कहा कि आगामी चुनावों में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें लोग मौन क्रांति कर एनडीए को सत्ता में ला सकते हैं।

विस चुनाव तमिलनाडु को भाजपा व आरएसएस से बचाने के लिए है : मणिकम

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अपनी जनसभा के दौरान हिंदी से अंग्रेजी में बात करके तमिलनाडु के लोगों का अपमान करना बंद कर दिया है। कांग्रेस सांसद ने तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की जीत की संभावनाओं पर भरोसा जताया और कहा कि ये चुनाव तमिलनाडु के गौरव की रक्षा के लिए हैं। टैगोर ने गुरुवार को एएनआई से कहा कि तमिलनाडु में भाजपा और एनडीए बुरी तरह हारने वाले हैं। कल उनकी रैली फ्लॉप रही... आमतौर पर प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं, लेकिन कल उन्होंने अंग्रेजी में बात की। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने हिंदी में बोलकर तमिलनाडु के लोगों का अपमान करना बंद कर दिया है। यह चुनाव तमिलनाडु को भाजपा-आरएसएस के हमलों से बचाने के लिए है।

ईरान के खिलाफ भारत के रुख पर विपक्ष का हमला

» भारत की विदेश नीति एकतरफा हो गई : चिदंबरम

» यूएनएससी में एनडीए सरकार के कदम से कांग्रेस बिफरी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को समर्थन करने के लिए सरकार की आलोचना की है। चिदंबरम ने भारत की मौजूदा विदेश नीति को एकतरफा करार दिया है।

चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की विदेश नीति अब निष्पक्ष नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि नई दिल्ली अब पूरी तरह अमेरिका और इस्राइल के पक्ष में खड़ी दिख रही है। चिदंबरम के अनुसार, भारत ने ईरान के हमलों की निंदा करने वाले प्रस्ताव को पेश करने में मदद की, लेकिन अमेरिका और इस्राइल के उन हमलों पर एक शब्द नहीं कहा जिनमें 1300 ईरानी लोग मारे गए।

उन्होंने बताया कि इन हमलों में 168 बच्चों की भी जान गई है। चिदंबरम ने सवाल उठाया कि क्या यही सही कूटनीति और निष्पक्ष विदेश नीति है? उन्होंने कहा कि रूस और चीन ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिया, जबकि भारत ने अमेरिका और 12 अन्य देशों का साथ दिया।

सुरक्षा परिषद में ये हुआ

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2817 (2026) पास किया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट पड़े, जबकि चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव में ईरान के उन हमलों की कड़ी निंदा की गई है जो उसने अपने पड़ोसी देशों पर किए। अमेरिका ने कहा कि ईरान हर दिशा में हमले कर रहा है। भारत सहित करीब 140 देशों ने इस टेक्स्ट को समर्थन किया। प्रस्ताव में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन पर हुए हमलों को गलत बताया गया। इसमें ईरान से मांग की गई कि वह रिहायशी इलाकों पर हमले तुरंत रोके। साथ ही, समुद्री व्यापार में दखल देना और उकसावे वाली कार्रवाई बंद करे। बहरीन ने इस अंतरराष्ट्रीय फैसले का स्वागत किया है।

अमेरिकी-इजरायली दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते पीएम मोदी : जयराम रमेश

कांग्रेस ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के एक दिन बाद शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर अब तक मौन हैं क्योंकि वह अपने अमेरिकी एवं इजराइली दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स% पर पोस्ट किया, ईरान के संवैधानिक प्रमुख अयातुल्ला खामेनेई की 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री मौन हैं। विदेश मंत्री मौन हैं। संसद में अब तक शोक प्रस्ताव तक नहीं रखा गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की सही तरह से निंदा की है लेकिन ईरान पर हुए अमेरिका-इजराइल के हमले पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है।कांग्रेस ने कहा कि यह भी याद रखा जाना चाहिए कि ईरान ब्रिक्स+ मंच का हिस्सा है, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है।

राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर किया था राजकीय शोक

जयराम रमेश ने कहा, मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब मोदी सरकार ने 21 मई 2024 को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी और संसद में एक जुलाई 2024 को, जब सत्र शुरू हुआ, शोक प्रस्ताव भी रखा गया था। अब यह हिचकिचाहट क्यों? उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एक कम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्रीअपने अमेरिकी और इजराइली दोस्तों को नाराज़ करने से बचना चाहते हैं।

ईरान ने किया अमेरिका एयरक्रॉफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर मिसाइल अटैक का दावा

» अमेरिका-इजरायल व ईरान जंग और तेज हुई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। ईरान ने शुक्र वार को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान पहुंचाने का बड़ा दावा किया है, जबकि अमेरिका ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। यह विवाद मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच सामने आया है।

ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) नेवी ने दावा किया कि उसके बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सटीक हमला किया। आईआरजीसी मुख्यालय के बयान के अनुसार, यह हमला ओमान सागर में ईरान की समुद्री सीमा से लगभग 340 किलोमीटर दूर किया गया। ईरानी मीडिया ने बताया कि हमले के बाद अमेरिकी पोत और उसका स्ट्राइक ग्रुप इलाके से भाग गया। आईआरजीसी ने दावा किया कि पोत अब ऑपरेशनल नहीं रहा। ईरान ने इसे अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन बताया है।

अमेरिका ने किया पलटवार

हालांकि, अमेरिकी सेना ने इन दावों को सिरे से नकार दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट किया कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत समुद्र से शक्ति प्रदर्शन जारी रखे हुए है।

ईरान ने इजरायल समेत खाड़ी देशों पर किया अटैक

आईआरजीसी के मुताबिक, उत्तरी इजरायल, किरयात शमोना, हदेरा, हाइफ़ा, बहरीन में अमेरिकी पांचवां बेड़ा और क्षेत्र में अन्य अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया गया है. ईरान ने खोर्रमशहर, खेबर, शेकान, फत्ताह, इमाद और क़द्र मिसाइलों के साथ-साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया।

इजरायल का दावा ईरान में 200 से अधिक ठिकानों पर किया हमला

अल जज़ीरा के मुताबिक, इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले दिन पश्चिमी और मध्य ईरान में 200 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है. वहीं, एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली ड्रोन ने बेरूत के बाहरी इलाके में एक रिहायशी अपार्टमेंट इमारत को निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से आधी रात से किए गए तीसरे बैलिस्टिक मिसाइल हमले के दौरान इजरायल के सबसे दक्षिणी शहर इलात में सायरन बजने लगे. प्रारंभिक आकलन से संकेत मिला है कि मिसाइल को संभवतः रोक लिया गया था किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

अरावली के बाद चंबल में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल अभयारण्य में धड़ल्ले से हो रहे अवैध रेत खनन के मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और वहां रहने वाले दुर्लभ वन्यजीवों पर मंडराते खतरे को देखते हुए स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लिया है। चंबल का यह संरक्षित क्षेत्र लंबे समय से अवैध खनन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है।

स्वतः संज्ञान लेकर जताई चिंता

जस्टिस विक्र म नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने स्पष्ट किया कि बड़े पैमाने पर हो रहा अवैध खनन वहां के लुप्तप्राय और दुर्लभ वन्यजीवों के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। कोर्ट के अनुसार, चंबल क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत संवेदनशील है, और अवैध खनन की गतिविधियां इसे स्थाई नुकसान पहुंचा रही हैं। चंबल अभयारण्य एक लंबे अरसे से रेत माफियाओं और अवैध खनन की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, जिसे रोकने में अब तक की चुनौतियां चिंताजनक रही हैं। बेंच ने कहा,हमने आज राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और खतरे में पड़ी जलीय वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर संज्ञान लिया है. हमने हाल की कुछ अख़बारों की रिपोर्टों और ट्रस्क द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर गौर किया है। इन रिपोर्टों में बताया गया है कि जिन पूरे संरक्षित क्षेत्रों में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है।

पीरियड्स लीव अनिवार्य करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार

» सीजेआई बोले- इससे महिलाओं का ही नुकसान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की मांग वाली याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ के सामने ये मामला उठाया गया था। ये याचिका शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- इस तरह की याचिकाए कभी-कभी महिलाओं को कमजोर या कमतर दिखाने का माहौल बना देती हैं. ऐसी याचिकाएं यह डर पैदा करती हैं कि मासिक धर्म महिलाओं के साथ कुछ बुरा होने जैसा है. इससे उन्हें ही नुकसान होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि यदि ऐसी व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई तो नियोक्ता महिलाओं को जिम्मेदार पद देने से हिचक सकते हैं।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि न्यायिक सेवाओं में भी महिलाओं को सामान्य ट्रायल जैसे महत्वपूर्ण काम सौंपने से बचा जा सकता है, जिससे उनके करियर पर असर पड़ सकता है।

असम चुनाव से पहले कांग्रेस ने तेज की रणनीतिक धार

केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा, असम गण परिषद ने भी लिया भाग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की और वहीं असम गण परिषद के नेता जयंत खाउंद पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस ने इस राजनीतिक घटनाक्रम को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष का संकेत बताया है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ आगामी असम विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। एक अलग घटनाक्रम में, सोमवार को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले असम में कांग्रेस को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला, जब असम गण परिषद (एजीपी) के पूर्व राष्ट्रीय वित्त सचिव जयंत खाउंद कुछ अन्य नेताओं के साथ पार्टी में शामिल हो गए।

खाउंद को पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल किया गया। इनमें असम प्रभारी और एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह अलवर, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और असम के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक डी के शिवकुमार, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और राष्ट्रीय सचिव मनोज चौहान शामिल थे।

हिमंता के नेतृत्व के खिलाफ असम में बढ़ा जन असंतोष : गोगोई

खाउंद का पार्टी में स्वागत करते हुए गोगोई ने कहा कि उनके जैसे जमीनी नेता का पार्टी में शामिल होना मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व के खिलाफ असम में बढ़ती जन असंतोष को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि असम में राजनीतिक परिवर्तन की लहर उठ रही है। उन्होंने कहा कि असम गण परिषद के जयंता खाउंद ने कुछ दिन पहले हमसे संपर्क किया था और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी... आज हम उन्हें और उनके साथियों को पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के मनमाने ढंग से काम करने, अयोग्य लोगों को राजनीति में बढ़ावा देने और वर्षों से सक्रिय राजनीति में कड़ी मेहनत करने वालों को दरकिनार करने के खिलाफ एक लहर उठ रही है। वे अपने साथ केवल भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को रख रहे हैं।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। विधि सलाहकार: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com |website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा